Institute of Chinese Studies ICS 中国研究所 DELHI

ANALYSIS

No. 62 September 2018

चीनी-अफ्रीकी विकास सहयोग में FOCAC का दम

Dr. Veda Vaidyanathan,
Research Associate, Institute of Chinese Studies
veda.vaidyanathan@gmail.com

चीन अफ्रीका सहयोग मंच यानी FOCAC ने 3 और 4 सितंबर को अपनी स्थापना की 18वीं सालगिरह मनाई. दिग्गजों की चमक-दमक से भरे इस भू-राजनैतिक (Geo-Political) समारोह का आयोजन बीजिंग में किया गया था.

अफ्रीकी न्यूज एजेंसियों की नजर में FOCAC आला दर्जे का कूटनीतिक आयोजन था. आयोजन की वजह से कुछ वक्त के लिए अफ्रीकी महाद्वीप जैसे अपने नेताओं से खाली हो गया था. अफ्रीकी देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष और बड़े नेता इस बड़े आयोजन में शामिल होने चले आए थे. आयोजन ऐसे वक्त में हुआ, जब चीन एक साथ कई चुनौतियों से मुकाबिल है. एक तरफ तो वह अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध (Trade War) में बुरी तरह उलझा हुआ है. दूसरी ओर इसके कुछ सहयोगी देश इसके ही कर्ज में डूबते नजर आ रहे हैं और इस वजह से इसे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही चीन के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा संतुलित करने का कठिन लक्ष्य है. (Africa 2018). इन हालातों के बावजूद तमाम विशेषज्ञ कमेटियों, मीडिया घरानों, बौद्धिकों, अकादमी और थिंक टैंक से जुड़े विशेषज्ञों ने दो दिन के आयोजन में जम कर हिस्सा लिया. आयोजन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उत्साह भरे उद्घाटन भाषण से शुरू हुआ (Xinhua 2018).

इस विशाल आयोजन में ताइपे को मान्यता देने वाले इस्वातिनी (पूर्व में स्वाजिलैंड) को छोड़ कर गांबिया, बुरकिना फासो, साओ तोम जैसे चीन के पाले में चले आए देशों के अलावा तमाम अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने पाले में चले आए इन देशों का खास तौर पर जिक्र किया और उनके FOCAC में शामिल होने पर जबरदस्त तारीफ हुईं. तालियां पिटवाई गईं.

पिछले कुछ समय से FOCAC न सिर्फ अफ्रीकी देशों और चीन के बीच बढ़ते संपर्क का अग्रदूत बन कर उभरा है बल्कि यह दोनों के बीच बढ़ती गतिविधियों का संकेतक भी बन गया है. फोरम यह भी बताता है कि चीन अफ्रीकी देशों को कितना तवज्जो दे रहा है. चीन की विदेश नीति ढांचे में अफ्रीकी देशों को मिल रही अहमियत का पता भी इस फोरम से चल जाता है. साथ ही यह चीन के क्षेत्रीय और वैश्विक नेता बनने की महत्वाकांक्षा भी जाहिर कर देता है.

फोरम में शी जिनपिंग ने कहा कि वह अफ्रीकी महाद्वीप का अब तक नौ बार दौरा कर चुके हैं. चार बार तो बतौर राष्ट्रपति वहां जा चुके हैं. उन्होंने अफ्रीकी देशों और चीन की दोस्ती और बदलते अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में दोनों के साझा इतिहास की चर्चा की. अपने संक्षिप्त भाषण में उन्होंने सात बार 'चीनी-अफ्रीकी समुदाय' का जिक्र किया. फोरम में भाषण के दौरान जिनपिंग जिस लहजे में बोले और बीजिंग घोषणापत्र के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे साफ है कि वैश्विक शासन व्यवस्था और ढांचे में चीन और स्पष्ट भूमिका निभाने के लिए तैयार है.

The ICS is an interdisciplinary research institution, which has a leadership role in the promotion of Chinese and East Asian Studies in India. The ICS Analysis aims to encourage debate and provide informed and balanced inputs for policy formulation and is based on extensive research and interactions with a wide community of scholars, experts, diplomats and military personnel in India and abroad.

फोरम का विषय था – China and Africa : Towards an Even Stronger Community with a shared Future through Win-Win cooperation. यह विषय चीन के रुख में परिवर्तन को साफ दिखा रहा था. यह कर्ज देने और लेने वाले देशों के बीच के संबंध से एक अलग रुख था. पश्चिमी देशों की अक्सर इस रुख की वजह से आलोचना होती रही है.

अफ्रीकी देशों के साथ संबध को लेकर चीन की नई नीति में 'मजबूत समुदाय' और 'साझा भविष्य' पर जोर दिया जा रहा है. जिस तरह से चीन की मौजूदगी अफ्रीकी देशों में बढ़ती जा रही है उससे ऐसा लग रहा है कि इस महाद्वीप में उसके हित लंबी अवधि के हैं. दोनों के मौजूदा पारस्परिक संबंधों को असंतुलित कह कर आलोचना करने वालों को चीन ने जवाब देने की कोशिश की है. चीन अफ्रीकी देशों में उद्योग, इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, व्यापार सुविधा, पर्यावरण हितैषी विकास, क्षमता निर्माण और हेल्थ केयर को बढ़ावा दे रहा है. साथ ही अफ्रीकी देशों और चीन के आम लोगों के बीच संपर्क को तवज्जो दी जा रही है. शांति कायम करने और सुरक्षा प्रयासों को रफ्तार देने की नीति पर भी काम हो रहा है.

अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग की गहराई और दायरा बढ़ा कर चीन दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वह नव-उपनिवेशवाद के समर्थन में कतई नहीं है और न ही यह तेल-गैस (हाइड्रोकार्बन) जरूरतों पर आधारित इकतरफा संबंध है. चीन विश्व समुदाय को यह बताना चाहता है कि वह अपने राष्ट्र चरित्र के मुताबिक ही अफ्रीका में विकास की नई कहानी लिख रहा है.

फोरम में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उद्घाटन भाषण एक तरह से वैश्विक नेताओं के लिए एक संदेश भी था. अफ्रीका में कई अन्य देश भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं. इस लिहाज से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने रिश्तों में 'फाइव नो (five no)'[1] रुख का जिक्र किया है. यानी इस रिश्ते में चीन जिन पांच चीजों को करने से बचेगा उनका जिक्र किया गया. उन्होंने इस नीति और कुछ दूसरे सुझावों का भी जिक्र किया जिनका इस्तेमाल अफ्रीका में सक्रिय दूसरे देशों के साथ रिश्तों में किया जाएगा. एक तरह से जिनपिंग ने अफ्रीका में पहले से अपना प्रभाव रखने वाले देशों के सामने भी चीन का रुख जाहिर कर दिया.

राष्ट्रपति जिनपिंग ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव, अफ्रीकन यूनियन एजेंडा और तमाम अफ्रीकी देशों के विकास कार्यक्रमों में समानता ढूंढने की अपील की है. और अफ्रीकी देशों की तरक्की के लिए अपने नए रुख को एक अहम माध्यम बनाया है.

हालांकि अफ्रीका में चीन की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि वह कब तक इन देशों के विदेशी मामलों और विकास के लिए अपनाए जाने वाले इनके अलग-अलग रास्तों की नीति में दखल देने से बचता रहेगा. इसके अलावा अफ्रीकी देशों को मदद देने में 'वन चाइना पॉलिसी' को समर्थन करने की राजनीतिक शर्त न थोपने की नीति अपनाने के वादे पर भी कुछ कहना मुश्किल है. चीन ने अपनी 'नो फाइव' नीति में अपना राजनीतिक स्वार्थ न साधने और अपनी मर्जी न थोपने का भी वादा किया है. चीन के इस रुख से यह सवाल पैदा होता है कि क्या उसने अफ्रीकी देशों के साथ अपने अब तक के संबंधों का पुनरीक्षण किया है और सचेत तौर पर यथास्थिति से अलग रुख अपनाने का फैसला किया है. या फिर वह अपने नए रुख की खासियतों को दुनिया के सामने जाहिर करना चाहता है.

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फोरम में अपने भाषण का इस्तेमाल चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में अफ्रीकी देशों की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करने के लिए भी किया. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चीन की ऐसी पहल के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों को एक सूत्र में बांधने की रफ्तार तेज करेगा करेगा और इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को पाट देगा. बीआरआई अफ्रीकन यूनियन एजेंडा और अलग-

---

[1] *Five-no रुख के पांच सूत्र*

1. अपनी परिस्थितियों के मुताबिक अफ्रीकी देशों की ओर से अपनाई गई विकास नीतियों में कोई हस्तक्षेप नहीं

2. अफ्रीकी देशों के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं

3. अफ्रीकी देशों पर चीनी मर्जी न थोपने का इरादा

4. अफ्रीकी देशों को मदद में राजनीतिक शर्तें थोपने से परहेज

5. निवेश में वित्तीय सहयोग के मामले में राजनीतिक स्वार्थ न साधने का इरादा

अलग देशों के विकास कार्यक्रमों में समानता ढूंढ़ने की शी जिनपिंग की अपील ने बीआरआई को अफ्रीकी महाद्वीप और चीन के बीच सहयोग आगे बढ़ाने का अहम जरिया बना दिया है. अब तक 37 अफ्रीकी देशों ने बीआरआई के विकास के लिए चीन के साथ समझौते पत्र पर दस्तख्त किए हैं (CGIN 2018).

वैसे फोरम में शी जिनपिंग के भाषण में शामिल जिस एक ऐलान का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, वह था चीन की ओर से अपनी आठ पहलकदमियों को पूरा करने के लिए अगले तीन साल में 60 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान. इस राशि से ये सभी आठ कदम पूरे करने की कोशिश की जाएगी. इनमें अफ्रीका और चीन के बीच व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए 5 अरब डॉलर का अफ्रीकन नॉन रिसोर्स आयात शामिल है. अफ्रीकी देशों के साथ कारोबार में संतुलन बुरी तरह चीन के पक्ष में झुका हुआ है और 5 अरब डॉलर के इस निवेश से अफ्रीका में घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. 60 अरब डॉलर के निवेश में 15 अरब डॉलर की वित्तीय मदद, ब्याज रहित कर्ज और रियायती कर्ज शामिल है. इसके अलावा इसमें 20 अरब डॉलर का लाइन ऑफ क्रडिट शामिल है. चीन-अफ्रीका विकास कार्यक्रम (CHINA-AFRICA DEVELOPMENT) के लिए बने विशेष फंड में 10 अरब डॉलर दिए जाएंगे. चीन सरकार के लोन का बड़ा हिस्सा कर्ज से लदे गरीब, अल्प विकसित, चारो ओर जमीन से घिरे विकासशील और छोटे द्वीपीय देशों को दिया गया था. यह कर्ज काफी बड़ा हो गया था. चीन के इन देशों के साथ 'राजनयिक रिश्ते' हैं, और इन समझौतों की अवधि 2018 में खत्म हो रही थी. चीन ने ऐसे देशों का कर्ज माफ कर दिया. चीन की कंपनियों को इस बात के लिए 'प्रेरित' किया गया कि वे अफ्रीकी महाद्वीप में अगले तीन साल में 10 अरब डॉलर का निवेश करें.

हालांकि चीन की ओर से FOCAC समिट में वित्तीय मदद के जो वादे किए गए हैं वे जोहानसबर्ग में किए गए वादे के जैसे ही हैं. लेकिन युन शुन जैसे विशेषज्ञ का मानना है कि अफ्रीकी देशों की चीन की ओर से वित्तीय मदद में मौजूदा छूट और प्राथमिकता पहले की तुलना में कम हो रही है. चीन को इस सहायता से जिस वित्तीय फायदे की उम्मीद की जा रही है उसकी अनिश्चितता बढ़ती जा रही है. कारोबारी नजरिये से ये आर्थिक मदद फायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं. शायद इस वजह से पहले की तुलना में चीन की ओर से अफ्रीकी देशों को वित्तीय मदद के मामले में मिल रही छूट और प्राथमिकताएं घट रही हैं. (Yun 2018 a) . कुछ दूसरे विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार और कमोडिटी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट, दोनों आगे चल कर चीन और अफ्रीका की आपसी गतिविधियों पर असर डालेगी. चीन और अफ्रीकी देशों के संबंधों पर काफी उत्साह जताया जा रहा है. दोनों के बीच साझा भविष्य, समान नियति और दोनों के फायदे वाले भाईचारे की बात की जा रही है.

लेकिन इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि भले ही चीन ज्यादातर अफ्रीकी देशों का कारोबारी साझीदार है लेकिन यहां उसका निवेश अभी भी काफी कम है. 2017 में अफ्रीका में चीन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 3.1 अरब डॉलर था. यह चीन के अंतरराष्ट्रीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सिर्फ 2.5 फीसदी है.

बहरहाल, FOCAC 2018 में अगर अफ्रीकी देशों की वित्तीय मदद के वादे से परे जाकर देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि अफ्रीका में चीन की गतिविधियों से जुड़े कामकाज का तौर-तरीका और लहजा बदला है. और इसने अफ्रीका में विकास गतिविधियों से जुड़े सहयोग के एक नए युग की शुरुआत की है.

चीन अब पारंपरिक विकास मॉडल से अलग हट चुका है,जो मुख्य रूप वित्तीय मदद पर आधारित होते थे. अब वह अफ्रीका में विकास गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नए तौर-तरीके अपना रहा है. और ये तौर-तरीके उसकी अपनी विकास प्रक्रिया के दौरान सीखे गए सबक पर आधारित हैं. अफ्रीका में अब चीन के विकास कार्यक्रम साउथ-साउथ को-ऑपरेशन और win-win पार्टनरशिप जैसे जुमलों से आगे निकल चुके हैं. वह अब अफ्रीका के क्षमता निर्माण (Capacity building) के लिए संसाधन और लोग दोनों झोंक रहा है. माना जाता है कि अफ्रीका में क्षमता निर्माण की नीति चीन के बरक्स भारत को यहां अंदर से ताकत देता है. इसलिए अफ्रीका में चीन की क्षमता निर्माण की गतिविधियों की प्रकृति समझना जरूरी है.

विकास गतिविधियों में चीन-अफ्रीका सहयोग

बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल के कृत्रिम आकाश के तले जिस FOCAC बीजिंग प्लान (2019-21) पर दस्तख्त हुए, उसमें भी क्षमता

निर्माण को प्राथमिकता के तौर पर लिया गया. इससे पहले के FOCAC में भी ऐसा ही हुआ था. इस बार चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि उनका देश अफ्रीका के साथ विकास गतिविधियों को अंजाम देने के ज्यादा से ज्यादा तौर-तरीके साझा करेगा. उन्होंने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए दस लुबेन (LUBAN) वर्कशॉप तैयार किए जाएंगे. साथ ही एक चीन-अफ्रीका इनोवेशन सेंटर बनेगा, जो उच्च क्षमता वाले एक हजार अफ्रीकियों को ट्रेनिंग देगा. यह कार्यक्रम युवाओं में इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देगा. यह चीन सरकार की ओर से दी जाने वाली 50 हजार स्कॉलरशिप और सेमिनार और कार्यक्रमों में ट्रेनिंग के 50 हजार मौके के अलावा होंगे. इनके लिए चीन अब 2000 नौजवान अफ्रीकियों को बुलाएगा. इसके अलावा चाइना-अफ्रीका रिसर्च एंड एक्सचेंज प्लान, चाइना-अफ्रीका मीडिया को-ऑपरेशन नेटवर्क, चाइना-अफ्रीका पीस एंड सिक्यूरिटी फोरम और स्किल ट्रांसफर और ट्रेनिंग के लिए कुछ और मंच विकसित किए जाएंगे.

हालांकि यह देखना होगा कि आगे चल कर इन कार्यक्रमों की संभावनाएं किस हद तक जाएंगी और ये कितने सफल होंगे. जोहान्सबर्ग में पिछले FOCAC सम्मेलन के दौरान बने चाइना-अफ्रीका इंडस्ट्रियल कैपिसिटी फंड ने 2016 में 10 अरब डॉलर के शुरुआती पूंजी से काम करना शुरू कर दिया था. माना जा रहा था कि यह 2018 तक 10 अरब डॉलर की परियोजनाओं की मदद करेगा. लेकिन अब तक इसने 5.42 करोड़ ड़ॉलर की छह परियोजनाओं को ही मंजूरी दी है. और इनमें से सिर्फ 2.48 करोड़ डॉलर की चार परियोजनाओं की ही फंडिंग की हुई है (Yun 2018 b).

हालांकि अफ्रीका की क्षमता विकसित करने की चीन की इच्छाशक्ति को चीनी कंपनियों की ओर से अपने मैन्यूफैक्चरिंग बेस अफ्रीकी महाद्वीप की ओर ले जाने के संदर्भ में देखना होगा.

वैसे चीन की ओर से अफ्रीका के क्षमता निर्माण की जो बात कही जा रही है उसके तहत यह वहां औद्योगीकरण को प्राथमिकता देता लग रहा है. वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक चीन रीजनल वोकेशनल एजुकेशन सेंटर और कैपिसिटी बिल्डिंग कॉलेजों की स्थापना करना चाह रहा है. इस योजना के तहत दो लाख अफ्रीकी टेक्निशियन्स अफ्रीका में और 40 हजार को चीन में ट्रेनिंग दी जाएगी. वैसे अफ्रीका की क्षमता विकसित करने की चीन की इस इच्छाशक्ति को चीनी कंपनियों की ओर से अपने मैन्यूफैक्चरिंग बेस अफ्रीकी महाद्वीप की ओर ले जाने के संदर्भ में देखना होगा.

मिसाल के तौर पर इथयोपिया के हवासा इंडस्ट्रियल पार्क में कुछ बड़ी चीनी टेक्सटाइल कंपनियां काम कर रही हैं. इनमें से कुछ ने यहां से अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए निर्यात भी शुरू कर दिया है. किलिनतो फार्मास्यूटिकल्स पार्क में भी जल्द ही भारत, चीन और कुछ दूसरे देशों की कंपनियां काम करना शुरू कर देंगी.यहां से विभिन्न अफ्रीकी देशों और दूसरे ग्लोबल मार्केट में दवा सप्लाई करने का लक्ष्य है. इथयोपिया में दवा निर्माताओं से बातचीत के दौरान उन चुनौतियों का खुलासा हुआ, जिनका इन्हें सामना करना पड़ता है. इनमें से एक चुनौती लगातार कुशल श्रमिकों की कमी बने रहना है. स्थानीय स्तर पर कुशल कामगारों की कमी है[2]. **2** इथोपिया सरकार कौशल की कमी को पूरा करने पर ध्यान दे रही है. उसने फार्मा कॉलेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है. उसने इसे देश के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है.

चीन और अफ्रीका के बीच सहयोग के ढर्रे पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि कृषि क्षेत्र इसका एक अहम पहलू है. अफ्रीका की कृषि क्षमता के निर्माण में चीन का निवेश महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर अफ्रीकी देश कृषि प्रधान हैं.कृषि एक श्रम सघन क्षेत्र है. इस लिहाज से खेती-बाड़ी में सहयोग न सिर्फ अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा बल्कि इससे रोजगार के मौके भी पैदा होंगे. चीन ने कृषि ज्ञान के प्रसार और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए अफ्रीकी देशों में 23 से ज्यादा कृषि टेक्नोलॉजी प्रदर्शन केंद्र – Agricultural Technology Demonstration centre (ATDC) बनाए हैं. चीनी कृषि मंत्रालय के मुताबिक इन ATDC ने एक लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया है. इससे फसलों की पैदावार 30 से 60 फीसदी बढ़ी है. (ChinaAfrica 2018). इनके अलावा चीन ने जांबिया की कृषि क्षमता को बढ़ाने के लिए रियायती लोन, कौशल प्रशिक्षण मुहैया

[2] *निजी साक्षात्कारों पर आधारित सितंबर, 2017*

कराया है.नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के बीच कृषि टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता के आदान- प्रदान के लिए समझौते किए गए हैं. कृषि को मजबूत करने के लिए 100 अफ्रीकी गांवों में इससे जुड़ी परियोजनाएं शुरू करने का विचार है. इसके तहत चीनी कृषि विशेषज्ञ अफ्रीका भेजे जाएंगे और चीन-अफ्रीका के कृषि विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग के लिए 10+10 सहयोग मैकेनिज्म बनाया जाएगा[3].

दरअसल, अब जोर इस बात पर है कि चीन-अफ्रीका सहयोग के मामले में अफ्रीकी देशों के संसाधनों और बाजार पर चीन की निर्भरता के बजाय इन देशों के साथ उसके व्यापार असंतुलन पर ध्यान केंद्रित करके देखा जाए.

चीन-अफ्रीका का साझा विकास सहयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र तक विस्तार लिए हुए है.वित्तीय सहायता के आंकड़ों के सहारे किए गए शु और चेंग के अध्ययन के मुताबिक चीन की ओर से मुहैया कराई जा रही वित्तीय सहायता ने अफ्रीकी देशों के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में अहम भूमिका निभाई है. चीनी मदद से यहां हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं. इन देशों में चीन की ओर से न सिर्फ मेडिकल उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ज्यादातर वित्तीय सहायता का इस्तेमाल इन्फ्रास्ट्रक्चर, उपकरण और दवा उपलब्ध कराने में हो रहा है (दवा मुहैया कराने से संबंधित 304 प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं). मेडिकल टीम से जुड़ी 189 परियोजनाएं चल रही हैं. (shajalal et al 2017) . हालांकि शु और चेंग का कहना है कि भले ही चीन अफ्रीकी हेल्थ सिस्टम को बनाने में मदद कर रहा है लेकिन इस दिशा में कुछ गंभीर चुनौतियां हैं. जैसे, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की इसमें नगण्य भागीदारी इन परियोजनाओं के स्थायित्व पर सवाल खड़ी करती है. इससे बीमारियों की रोकथाम, हेल्थ एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने जैसे विषयों पर काम नहीं हो पा रहा है.

अफ्रीका में उद्योग, कृषि और हेल्थ सेक्टर में व्यावसायिक प्रशिक्षण (वोकेशनल ट्रेनिंग) के अलावा चीनी अफ्रीकी सहयोग का शिक्षा के क्षेत्र में फोकस है. यह सहयोग के अन्य क्षेत्रों में से एक है. अफ्रीका की क्षमता में बढ़ोतरी में मदद करना तेजी से उभरते अफ्रीकी-चीन सहयोग ढांचा का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है. चीन-अफ्रीका सहयोग को अफ्रीकी देशों के संसाधनों और बाजार पर चीन की निर्भरता के नजरिये से देखे जाने के बजाय फोकस इस बात पर है कि चीन के साथ इनके व्यापार घाटे को कैसे कम किया जाए. इसे एक ग्लोबल ताकत के संभावना से भरे गतिशील अफ्रीका के साथ सहयोग के शुरुआती चरणों के तौर पर देखा जा रहा है. चीन अब यहां अपनी ताकत का इस्तेमाल बेहतर सौदे और समझौते में कर रहा है कि ताकि अफ्रीकी देशों में विकास प्रक्रियाओं की बुनियादी खामियों को दूर किया जा सके.

हालांकि अफ्रीकी महाद्वीप में चीन के समग्र विकास सहयोग को यहां इसकी बढ़ती भूमिका पर चल रहे व्यापक विमर्श और बहस के दायरे में भी देखा जाना भी अहम है. मोटे तौर पर देखा जाए तो अफ्रीका में चीन की गतिविधियों को लेकर दो विमर्श चल रहे हैं. इनमें से एक में कहा जा रहा है कि अफ्रीका को अपने यहां चीन की बढ़ती मौजूदगी पर सावधान रहना चाहिए. यह बात अफ्रीकी देशों को दिए जाने वाले कर्ज की प्रकृति और शर्तों और इसे चुकाने में उनकी नाकामी के संदर्भ में कही जा रही है. कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर चीन का श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जे का मामला हाल में सुर्खियों में रहा था. जाम्बिया की ओर से भी कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर लुसाका में केनेथ कोंडा एयरपोर्ट पर चीन के कब्जे की बात भी सामने आई थी. (हालांकि बादा में जांबिया ने इसका खंडन किया था) . चीन-अफ्रीका सहयोग में इस तरह के संदर्भ दिए जाते हैं. (Lusaka Times 2018a 2018b). दूसरी ओर यह भी तल्ख सच्चाई है कि अफ्रीकी देशों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है. साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक अंतरराष्ट्रीय कर्जदाता संस्थाएं या अमेरिका और यूरोप की ओर से दिए जाने जाने वाले कर्ज शर्तों से लदे माने जाते हैं. इसे हासिल करने के लिए लंबी प्रक्रिया होती और कई दफा इसके मिलने की भी गारंटी नहीं होती है. इन

[3] *Ministry of ForeignAaffairs of People's Republic of China. Forum on China-Africa Cooperation Bejing Action Plan (2019-21,) Beijing.*

स्थितियों में चीन ने खुद को अफ्रीका के विकास में एक अहम पार्टनर के तौर पर स्थापित कर लिया है.

अफ्रीका के विकास में चीन की बेहतरीन डिलीवरी और मुहैया कराए गए अच्छे-खासे संसाधनों ने इन देशों के सामने एक बेहतरीन विकल्प खड़ा कर दिया है. अमेरिका, यूरोप या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की मदद के विकल्प के तौर पर चीनी संसाधनों का विकल्प इतना मजबूत है कि इसके जोखिम कमजोर पड़ जाते हैं. हालांकि चीन को अफ्रीकी देशों के सामने खुद को एक मजबूत गैर पश्चिमी विकल्प के तौर पर विकसित होने में काफी वक्त लगा है. यह चीनी नेताओं की लगातार अफ्रीकी देशों की यात्राओं और उनके साथ विचार-विमर्श से संभव हुआ है. पिछले एक दशक में चीन के नेता 43 अफ्रीकी देशों का 79 उच्चस्तरीय दौरे कर चुके हैं. इनमें से 26 इस क्षेत्र के सबसे गरीब देश हैं (Development Reimagined 2018).

निष्कर्ष

चीन अफ्रीका में मानव और सांस्थानिक क्षमता बढ़ाने की नीति पर चलना चाहता है. उसका यह नया और व्यापक नजरिया पहले के निराशावादी नैरेटिव से उलट है. चूंकि ज्यादातर अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में है, इसलिए माना जा रहा है कि विकास को लेकर सहयोग दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होना चाहिए.चीन-अफ्रीका सहयोग परिदृश्य के सबसे बड़े बदलावों में से एक है- इसमें और ज्यादा उप-राष्ट्रीय तत्वों के शामिल होने की उम्मीद में इजाफा. चूंकि यह माना जाता है कि चीन में सरकारी कंपनियों का काफी वर्चस्व है. इसलिए अफ्रीकी बाजार में छोटे और मझोले उदयोगपति और सूक्ष्म उद्योगों का प्रवेश इसकी नीतियों में प्राथमिकता में होगी. यह मौजूदा आपसी आर्थिक गतिविधियों को विविधता देगा. हालांकि अफ्रीका और चीन के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के दूसरे नतीजे भी निकल सकते हैं. अगर चीन की आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी होती है तो इसका अफ्रीका के विकास पर नकारात्मक असर पड़ेगा.

बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत अफ्रीकी देशों में विकास के लिए सहयोग का दायरा और बढ़ेगा. क्योंकि चीन की इस बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत इन देशों को और ज्यादा वित्तीय सहायता मिलेगी. हालांकि FOCAC 2018 में बीआरआई को 'अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए मंच' के तौर पर पेश किया गया. लेकिन सच्चाई यही है कि अफ्रीकी देशों में चीन की ओर से बड़े पैमाने पर तैयार किए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर उन्हें और ज्यादा कर्ज से लाद देंगे. और इनमें से कई देश इन्हें चुकाने में नाकाम साबित हो सकते हैं. इसके अलावा यह भी साफ नहीं है कि ये परियोजनाएं आर्थिक तौर पर कितनी कारगर होंगी. कर्ज डिफॉल्ट के नतीजे क्या होंगे, इस पर भी अस्पष्टता बनी हुई है.

चीन-अफ्रीका के इस आपसी संबंध पर नजर रखना और इसका अध्ययन आखिर क्यों बेहद जरूरी है. यह इसलिए कि इस संबंध में भागीदार चीनी तत्वों का दायरा बढ़ता जा रहा है और उनके हित भी व्यापक होते जा रहे हैं. जबरदस्त संभावनाओं और युवा आबादी से लैस अफ्रीका एजेंसियां दोनों देशों के संबंधों में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में काम कर सकती हैं. इन कोशिशों की वजह से दोनों के बीच बेहतर सौदे हो सकते हैं और नतीजतन उनके विकल्पों में भी विविधता आएगी.■

REFERENCES

AfricaNews. 2018. 'Handful African presidents not attending 2018 FOCAC summit in China', 3 September, http://www.africanews.com/2018/09/03/handfulafrican-presidents-not-attending-2018-focacsummit-in-china// (accessed on 10 September 2018).

China Global Television Network (CGTN). 2018. 'China signs MOUs with 37 African countries, AU on B&R development', 8 September, https://africa.cgtn.com/2018/09/08/china-signsmous-with-37-african-countries-au-on-brdevelopment/ (accessed on 11 September 2018).

ChinaAfrica. 2017. 'Capacity Building Agenda', 9 November, http://www.chinafrica.cn/Africa/201711/t2017 1108 _800109379.html (accessed on 12 September 2018).

Development Reimagined. 2018. 'Who does China prioritize? Our first infographic sheds some light', 30 January, https://developmentreimagined.com/2018/01/30/wh o-does-china-prioritise-our-first-investigation/ (accessed on 9 September 2018).

Lusaka Times. 2018a. 'China to take over ZESCO – Africa Confidential', 4 September, https://www.lusakatimes.com/2018/09/04/china-to-take-over-zesco-africa-confidential/ (accessed on 10 September 2018).

Lusaka Times. 2018b. 'Kenneth Kaunda International Airport will not be surrendered to China-Dora Siliya', 10 September, https://www.lusakatimes.com/2018/09/10/kennethkaunda-international-airport-will-not-besurrendered-to-china-dora-siliya/ (accessed on 11 September 2018).

Shajalal, Mohon, Junfang Xu, Jun Jing, Madeleine King, Jie Zhang, Peicheng Wang, Jennifer Bouey and Feng Cheng. 2017. China's engagement with development assistance for health in Africa. London: Global Health Research and Policy. Xinhua. 2018. 'Full text of Chinese President Xi Jinping's speech at opening ceremony of 2018 FOCAC Beijing Summit', 3 September, http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/03/c_129946189.htm (accessed on 9 September 2018).

Yun Sun. 2018a. 'China's 2018 financial commitments to Africa: Adjustment and recalibration' Brookings. 5 September, https://www.brookings.edu/blog/africa-infocus/2018/09/05/chinas-2018-financialcommitments-to-africa-adjustment-andrecalibration/ (accessed on 12 September 2018).

Yun Sun. 2018b. 'Foresight Africa viewpoint – China's engagement in Africa: What can we learn in 2018 from the $60 billion commitment?' Brookings, 30 January, https://www.brookings.edu/blog/africa-infocus/2018/01/30/foresight-africa-viewpointchinas-engagement-in-africa-what-can-we-learn-in2018-from-the-60-billion-commitment/ (accessed on 9 September 2018).

इस विचलेषण में मौजूद विचार लेखखका के हैं। इंस्टीट्यूट केविचार सेइसका मेल खाना जरूरी नहींहै।.

ICS ANALYSIS *Back Issues*

Issue No/ Month	Title	Author
No. 61 | Sep 2018	Shades of India-China Energy Geopolitics: From Petroleum to Renewables	Nandakumar Janardhanan
No. 60 | Sep 2018	China's South China Sea Strategy	Saurav Sarkar
No. 59 | Jun 2018	When Bose was in China!	Nirmola Sharma
No. 58 | Jun 2018	Spring Time in the Korean Peninsula after a Long Winter?	Vishnu Prakash
No. 57| May 2018	Chinese Investments in Europe	Anil Wadhwa
No. 56 | May 2018	China's Crackdown on Crime and Corruption with Tibetan Characteristics	Tshering Chonzom
No. 55 | May 2018	Summit Diplomacy and Denuclearizing North Korea	Sandip Mishra
No. 54 | Apr 2018	The United States-China Trade Confrontation and Implications for India	Sharmila Kantha
No. 53 | Mar 2018	Sino-Nepalese Engagements in the Himalayan Borderland	Diki Sherpa
No. 52 | Jan 2018	China's Quest for Global Leadership	Shyam Saran

Principal Contributors to ICS Research Funds

TATA TRUSTS
Development Partner

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA

INDIAN COUNCIL OF
SOCIAL SCIENCE RESEARCH

GARGI AND VIDYA
PRAKASH DUTT FOUNDATION

JAMNALAL BAJAJ
FOUNDATION

PIROJSHA GODREJ TRUST

ICS PUBLICATIONS

ANALYSIS

A short brief on a topic of contemporary interest with policy-related inputs.

OCCASIONAL PAPER

Platform for ongoing research of the ICS faculty and associates.

MONOGRAPH

Authored by the faculty, also emerging from research projects and international conferences.

WORKING PAPER

Draft paper of ongoing research

JOURNAL

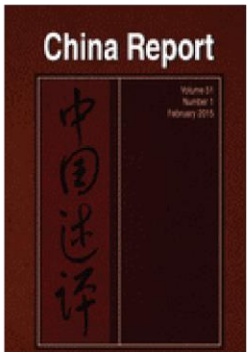

In its 54th year of publication, *China Report* is a quarterly refereed journal in the field of social sciences and international relations. It welcomes and offers a platform for original research from a multi-disciplinary perspective in new and emerging areas by scholars and research students.

INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
8/17, Sri Ram Road, Civil Lines,
Delhi-110054, INDIA
Tel: +91 (0) 11 2393 8202
Fax: +91 (0) 11 2383 0728
http://www.icsin.org/
info@icsin.org

twitter.com/ics_delhi
in.linkedin.com/icsdelhi
youtube.com/ICSWEB
facebook.com/icsin.delhi
soundcloud.com/ICSIN
instagram.com/icsdelhi